मूलनिवासी सन्देश
व्यूपाइंट

अंक : 10
जुलाई, 2019

संस्थापक सम्पादक : स्मृतिशेष आर. पी. सराफ

लोकतंत्र एवं चुनाव का जनता से सरोकार

पर्यावरणीय संवर्द्धन एवं चहुंमुखी जन-सशक्तिकरण आधारित लोकतंत्र हमारे ग्रह के जैव-जीवन एवं समस्त मानव प्रजाति की आपातकालीन आवश्यकता

जबकि

वर्तमान लोकतंत्र की अस्पष्ट और भ्रान्त धारणाओं ने कारपोरेटों (धनवानों), भ्रष्ट तथा अपराधी प्रवृत्ति के राजनीतिज्ञों को हमारे ग्रह के प्राकृतिक पर्यावरण को बर्बाद करने एवं जैव-सामाजिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाने का अवसर प्रदान किया 01

वंचितों, दलितों, बहुजनों और आदिवासियों की गरीबी भारत में विद्यमान व्यवस्था के कारण हैं 19

सहयोग राशि : 20 रुपये

Scanned with CamScanner

लोकतंत्र एवं चुनाव का जनता से सरोकार

पर्यावरणीय संवर्द्धन एवं चहुंमुखी जन-सशक्तिकरण आधारित लोकतंत्र हमारे ग्रह के जैव-जीवन एवं समस्त मानव प्रजाति की आपातकालीन आवश्यकता

जबकि

वर्तमान लोकतंत्र की अस्पष्ट और भ्रान्त धारणाओं ने कारपोरेटों (धनवानों), भ्रष्ट तथा अपराधी प्रवृत्ति के राजनीतिज्ञों को हमारे ग्रह के प्राकृतिक पर्यावरण को बर्बाद करने एवं जैव-सामाजिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाने का अवसर प्रदान किया

I

हमारा पहला सवाल है कि ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन की चुनौती तथा परमाणु, रासायनिक एवं जैविक हथियारों से लैस विश्व साथ ही मानव समाज के कारपोरेट अमानवीयकरण की घातक (जीवन या मौत की) चुनौती का मुकाबला कैसे करें?

बहुत ही आसान शब्दों में कोई कहे कि मुझे और आपको शुद्ध हवा चाहिए, हमारे ग्रह के प्रत्येक जैव-जीवन को शुद्ध हवा चाहिए। हमारे ग्रह के प्रत्येक मानव एवं जीव-जगत को शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन..... इत्यादि कुछ चाहिए।

क्या कोई देश या उसकी सरकार (चाहे महाशक्ति अमेरिका ही क्यों न हो) वर्तमान लोकतंत्र के चलते अपने देश के नागरिकों या जीवों को शुद्ध हवा खिला सकती है? निस्संदेह, नहीं।

फिर प्रत्येक देश का नागरिक क्या करे कि उसे कम से कम शुद्ध हवा मुहैया हो सके। या दूसरे शब्दों में विश्व के नागरिक इसके लिए क्या करे?

यह सवाल अटपटा और नया लग सकता है परन्तु इस सवाल का जवाब खोजे बगैर सिर्फ चुनावों के जरिए सरकारें बदलकर हम इस धरती पर जिन्दा नहीं रह सकते हैं।

Scanned with CamScanner

इस ग्रह पर जैव-जीवन को यह खतरा क्यों और कैसे आया है—यानि इसका कारण क्या है तथा इसका निवारण कैसे हो सकता है।

क्या इसका कारण कोई मानव की व्यक्तिगत स्तर पर किसी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की गलती में निहित है या राष्ट्रीय—अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की गलती की वजह से है अथवा हमारे औद्योगिक युग का एजेण्डा ही अप्रासंगिक और जैव-जीवन विरोधी है।

इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश में हमें हमारे ग्रह के जैव-जीवन एवं मानव के अस्तित्व के इतिहास पर नजर डालने की जरूरत है।

हमारे वर्तमान मानवीय ज्ञान-विज्ञान के आधार पर हम कह सकते हैं कि ब्रह्माण्ड में केवल पृथ्वी ग्रह का पर्यावरण ही जैव-जीवन का आधार बना। इस पृथ्वी पर हमसे (मानव जीवन से) पहले भी बहुत से जीव-जन्तु पैदा हुए और अपने पर्यावरण के साथ-साथ आपसी पूरकता (एकता व संघर्ष दोनों के संतुलन) में इतिहास के किसी काल में अपना जीवन पूरा किया। कुछ लाख साल पहले मानव ने भी एक जीव-प्रजाति के रूप में हमारे ग्रह पर पदार्पण किया। मानव शास्त्र (एन्थ्रोपोलोजी) के अनुसार शुरूआत में मानव जाति की पर्यावरण एवं जीव जन्तुओं के साथ पूरकता (एकता व संघर्ष का संतुलन) का संबंध काफी मुश्किलों से गुजरा एवं इसी पूरकता को कायम रखने एवं अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए मानव को अपने दिमाग का अधिकतम उपयोग करना पड़ा। इसी का परिणाम एक तरफ मानव द्वारा प्रकृति के नियमों को जानने एवं औजार बनाने तथा सीधे खड़े होकर हाथों का प्रयोग औजारों सहित करने में निकला तो दूसरी तरफ मानव-मानव के बीच सामाजिक संबंधों के (एकता और संघर्ष के जरिए अन्तरक्रिया से) आगे बढ़ने में निकला।

उपरोक्त ऐतिहासिक प्रक्रिया में मानव समाज विज्ञान-तकनीक के धीरे-धीरे विकास के साथ गणों, कबीलों, दास मालिकों, कृषिकारी, सामंती समाजों एवं राष्ट्रीय राज्यों से अन्तरनिर्भर विश्व व्यवस्था (अन्तरनिर्भर राष्ट्रीय राज्यों सहित) में प्रवेश कर चुका है।

Scanned with CamScanner

वर्तमान समय में मानव प्रजाति दूसरे जीव-जगत एवं समस्त जैव-विविधता के साथ पूरकता (जिसमें एकता एवं संघर्ष का सन्तुलित रूप था) की बजाय गैर-पूरकता (यानि पूर्ण नियंत्रण) का रुख अपना चुकी है। अब यह दूसरे जैव-जगत से ज्यादा ताकतवर बन चुकी है एवं स्वयं को बुद्धिमान और श्रेष्ठ होने का दर्जा देते हुए इन पर पूर्ण नियंत्रण का ठेका ले चुकी है। यह नियंत्रण करने की मानसिकता एक तरफ जहां समस्त प्रकृति को नियंत्रित करने की दिशा लिए हुए है तो दूसरी तरफ तथाकथित श्रेष्ठ, बुद्धिमान, सभ्य, कारपोरेट, नेता, पार्टी आदि 'अतिमानवों' द्वारा समस्त आम नागरिकों को नियंत्रित करने का एजेण्डा और व्यवस्था कायम कर चुके हैं। दुनिया के आम नागरिकों को व्यक्तिवाद, सम्प्रदायवाद, कारपोरेटवाद, राष्ट्रवाद, महाशक्तिवाद और मानव केन्द्रित वाद आदि असंख्य पूंजी के एजेण्डे की गुटबाजियों में धकेल कर उन पर वैचारिक कुछ 'श्रेष्ठ' मानव कायम कर चुके हैं। और ये समस्त मानव प्रजाति को फूट डालो राज करो की पद्धति में ढाल चुके हैं। ये 'श्रेष्ठ' शासक कारपोरेट लोग अब पृथ्वी पर 'भगवान' बन गये हैं।

तभी तो दुनिया के केवल 26 कारपोरेट कम्पनियों के पास दुनिया की निचली गरीब आधी आबादी से भी ज्यादा धन इकट्ठा हो चुका है। भारत की निचली 50 प्रतिशत आबादी के पास मात्र इतना धन है जितना भारत के 9 अरबपतियों के पास है जबकि भारत की 1 प्रतिशत धनवान आबादी के पास देश की कुल आय (जी डी पी) का 52 प्रतिशत हिस्सा है। यही दुनिया की कारपोरेट कम्पनियां अपने मुनाफे के लिए महाशक्तिवाद, राष्ट्रवाद आदि गुटबाजियों का सहारा लेकर इस धरती पर समस्त युद्ध सामग्री (रासायनिक-जैविक हथियार सहित लड़ाकू विमान, टैंक, तोप, बन्दूकें इत्यादि) बनाती हैं और रासायनिक, जी.एम. की औद्योगिक खेती को आगे लाती है और औद्योगिक गलियारों का सर्वनाशी 'विकास' की योजना बनाती है। यही कम्पनियां दुनिया के देशों के राष्ट्रीय राजनीतिक लोकतंत्र एवं चुनाव का प्रबंधन अपने पैसों के बल पर राजनीतिक पार्टियों एवं मीडिया के माध्यम से सम्पन्न करवाती हैं। अब ये कम्पनियां साम-दाम-दंड-भेद एवं मीडिया व

Scanned with CamScanner

ई.वी.एम. आदि तकनीक तथा पूंजीवादी समाजशास्त्रीय धारणाओं के बल पर दुनिया के लोगों का जीवन नियंत्रण में ले चुकी हैं।

याद रहे कि सन् 1970 के बाद के इस कारपोरेट विकास ने सन् 2018 तक (केवल 48 वर्षों में) हमारे ग्रह की जैव-विविधता का 52 प्रतिशत नुकसान कर दिया है। यू.एन.डी.पी. के आंकड़ों के मुताबिक 60 प्रतिशत जंगली जानवरों, 52 प्रतिशत पालतू पशुओं, 50 प्रतिशत समुद्री जैव-जीवन और 52 प्रतिशत भूमि की लवण शक्ति तक का नुकसान कर दिया है।

इस प्रकृति विरोधी, मानव-विरोधी, जैव-जीवन चक्र विरोधी विकास ने हमारी पृथ्वी के समस्त प्राकृतिक संसाधनों को अन्तिम सीमा तक निचोड़ डाला है जिसका प्रमुख उदाहरण ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना है। वैज्ञानिक आंकड़े दर्शाते हैं कि औद्योगिक सभ्यता के शुरू से लेकर सन् 1918 तक 2000 अरब टन जीवाष्म ईंधन (पैट्रोल, कोयला, गैस इत्यादि) जलाया जा चुका है जिससे वायु प्रदूषण 280 पी पी एम से 415 पी पी एम पहुंच चुका है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अब हम अगर 1000 अरब टन और फोसिल फ्यूल (जीवाष्म ईंधन) जला डालते हैं तो वायु प्रदूषण 450 पी पी एम की अन्तिम सीमा पार हो चुकी होगी जिससे पृथ्वी का औसत तापमान 2° सैल्सियस की दहलीज पार कर चुका होगा। ऐसे वक्त में ध्रुवों की बर्फ की परत कमजोर पड़ चुकी होगी तथा साईबेरिया एवं ध्रुवों के पास के इलाकों की परमाफ्रोस्ट (बर्फीली पक्की परत) से मिथेन का निकलना शुरू हो चुका होगा। तब पृथ्वी पर जीवन का बने रहना नामुमकिन बन जायेगा।

ऐसी परिस्थिति में मैं और आप तथा समस्त पृथ्वीवासी क्या सोच बनाएं, क्या करें और कैसा संगठन बनाएं—यानि क्या कार्यक्रम (एजेण्डा) अख्तियार करें।

प्रथम हम सब पृथ्वीवासी पक्का सोच बनाएं कि इस ग्रह के पर्यावरण को मानव सहित समस्त जीव-जगत (जीवों एवं वनस्पति) के लिए मुफीद बनाए रखे बगैर हमारा जीना संभव नहीं है। साधारण शब्दों में साथ जियेंगे-साथ मरेंगे—यानि पृथ्वी के जीवन और उसके पर्यावरण को बचाए बगैर हम (मानव) नहीं बच सकते हैं। हम पृथ्वी के मालिक (भगवान) नहीं बल्कि

Scanned with CamScanner

हम एक अंग (अंश) मात्र है, हम सबसे श्रेष्ठ-बुद्धिमान नियंत्रणकर्ता नहीं बल्कि एक अलग (विशिष्ट) गुण वाले जीव मात्र जरूर हैं। जैसे दुनिया का हर जीव या निर्जीव अलग विशिष्टता रखता है। अपने तरीके से मजबूत भी होता है परन्तु कुल मिलाकर उसकी मजबूती दूसरे घटनाक्रम के साथ पूरकता में ही होती है। यही स्थिति मानव समुदाय की है। मानव समाज का आधार भी प्रकृति-पर्यावरण एवं स्वयं मानव समुदाय की पूरकता में निहित है, नियंत्रण में नहीं है।

द्वितीय, मानव को प्रकृति ने स्पष्टतया दोहरे स्वभाव (जैव-सामाजिक) वाला बनाया है। यानि एक तरफ प्रत्येक मनुष्य के लिए जरूरी है कि वह अपना खाना-पीना, दवाई, निंद्रा लेना-आराम करना इत्यादि जैविक क्रियाएं स्वयं करे जबकि अपने औजारों-तकनीक और ज्ञानार्जन का कार्य सामाजिक तौर पर काम के बंटवारे के तौर पर पूरा करे। यही कारण है कि आज की दुनिया विश्व स्तर के ज्ञान-विज्ञान एवं तकनीक का उपयोग (अथवा दुरुपयोग) करने के लिए लोकल से ग्लोबल स्तर पर एक ही तरह से आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय नियमों को लागू करने के लिए एक विश्व स्तरीय ढांचा व व्यवस्था कामय किए हुए है। वर्तमान मानवीय सामाजिक व्यवस्था राष्ट्रीय नहीं बल्कि विश्व स्तरीय है। तथाकथित राष्ट्रीय व्यवस्था इस विश्व व्यवस्था की उप व्यवस्था (अथवा अंश मात्र) है। अतः मानव जाति को समस्त प्राकृतिक पर्यावरणीय संसाधनों को जीवन चक्र के उपयोगी बनाने के लिए अपनी विश्व सामाजिक व्यवस्था को प्रकृति-मानव केन्द्रित एजेण्डे पर पुनरसंगठित करनी होगी।

बहुत साफ है कि ऐसी प्रकृति-मानव केन्द्रित व्यवस्था पर्यावरणीय हितों के साथ मानवीय मसलों को जोड़ने वाली एक विश्व व्यवस्था होगी, एक विश्व जो पर्यावरणीय और मानवीय आवश्यकता के अनुकूल होगा, ना कि मानवीय लालच अभिमुख, एक विश्व जो युद्धविहीन और सीमाविहीन होगा, एक विश्व जो टिकाऊ, समता, उत्पादकता, चहुंमुखी पारदर्शिता के विकास मॉडल पर आधारित होगा जो आय में केवल मात्र 1:2 के अन्तर को स्वीकृति देगा तथा सभी वंचित, गरीब, बेरोजगार आदि के लिए सामाजिक सुरक्षा एक मूल अधिकार के रूप में सुनिश्चित करेगा तथा एक विश्व जो

Scanned with CamScanner

पर्यावरणीय एवं मानवीय मूल्यों द्वारा पहचाना जाएगा। व्यवस्थागत परिवर्तन की चाबी यही एजेण्डा बन सकता है।

II

जबकि वर्तमान लोकतंत्र और उसकी चुनावी प्रक्रिया की अस्पष्ट, संकीर्ण और भ्रांत धारणाओं ने दुनिया के कारपोरेटरों (धनवानों) तथा भ्रष्ट एवं अपराधी प्रवृत्ति के राजनीतिज्ञों को हमारे ग्रह के प्राकृतिक पर्यावरण को बर्बाद करने और जैव-प्रजातियों को भारी संकट में डालने तथा मानव जाति को बेहिसाब रफ्तार से बदनीयत रास्ते पर धकेल कर आत्मघाती मंजर पैदा कर दिया है।

वर्तमान डेमोक्रेसी इसकी प्रकृति, मानदंड और व्यवहार

डेमोक्रेसी की परिभाषा डेमो (यानि लोग) और क्रेसी (यानि शासन) के ग्रीक शब्द डेमोक्रेसिया से आयी है यानि जनता का शासन। यह डेमोक्रेसी की धारणा प्राचीन ग्रीक के कुछ शहरी राज्यों से पैदा हुई है जहां शासन का संचालन चुने हुए प्रतिनिधियों के बजाए सीधे सम्पूर्ण नागरिक इदारे करते थे। वहां इस प्रकार का शासन संभव था क्योंकि शहरी राज्य की जनसंख्या थोड़ी थी तथा महिलाओं और दासों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था। दास-मालिकों ने अपने शासन को जनता का शासन कहकर वास्तविकता को विकृत किया।

यह सामान्य तथ्य है कि चल रही डेमोक्रेसी सीधे जनता के शासन को अभिव्यक्त नहीं करती। यह मात्र लोगों के प्रतिनिधियों का शासन है। लोगों को केवल एक ही अधिकार है कि वे अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय स्तर की चुनाव प्रक्रिया के जरिए चुनते हैं। इसके आगे लोगों को विश्व स्तर पर कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है तथा आर्थिक व सांस्कृतिक या पर्यावरणीय मुद्दों पर स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का कोई अधिकार आम जनता को नहीं है।

उदाहरण के लिए, किसी भी देश की जनता (या दुनिया की जनता) आर्थिक प्रबंध में कारपोरेट कम्पनियों के बजाए को-ऑपरेटिव आधारित या

Scanned with CamScanner

डेमोक्रेटिक जन नियंत्रण आधारित करने का सोच भी नहीं सकती है। इसी तरह वर्तमान मीडिया और शिक्षा प्रणाली से लेकर समस्त ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय पहलुओं पर कारपोरेट नियंत्रण हटाने के विचार को वर्तमान व्यवस्था अव्यवहारिक समझती है। विश्व के कारपोरेट बुद्धिजीवी ऐसे किसी भी सोच को अव्यवहारिक ही नहीं बल्कि अराजकतावादी, कोरा आदर्श या केवल मात्र दिवास्वप्न करार देते हैं।

अब हम हमारे देश की आजादी के इतिहास तथा आज की राष्ट्रीय राजनीतिक डेमोक्रेसी और इसकी चुनावी प्रक्रिया पर नजरसानी करते हुए, हालिया लोकसभा चुनाव–2019 को उपर्युक्त नजरिये से समझाने की कोशिश करते हैं।

सबसे पहले हम भारत देश या राष्ट्र बनने या तथाकथित राष्ट्रीय आजादी के इतिहास पर नजर डालें तो समझ सकते हैं कि हमारे भारतीय उपमहाद्वीप की जनता को आम तौर पर दुनिया के शासकों एवं खास तौर पर अंग्रेज शासकों द्वारा सिखाया गया कि आप अगस्त 1947 में पूर्ण स्वतंत्र (सार्वभौम राष्ट्र) बन चुके हैं। भारतीय उपमहाद्वीप को जनता ने समझा कि अब हमारे पर विश्व राजनीति, विश्व अर्थनीति एवं विश्व संस्कृति का असर नहीं के बराबर है। अब हम आजाद हो गये हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की सभी राजनीतिक पार्टियों (खास करके कांग्रेस, मुस्लिम लीग इत्यादि) ने ढोल पीटकर जनता को समझाया कि एक ब्रिटिश कम्पनी ने हमें गुलाम बना लिया था अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। परन्तु इतिहास गवाह है चाहे भारत हो या पाकिस्तान (या दुनिया का अन्य कोई देश) ठीक इसके उलट दुनिया की कम्पनियों की अगुवाई में आर्थिक विकास एवं वीटो पॉवर वाली शक्तियों के राजनीतिक प्रभुत्व में तथा रक्षा के नाम पर हथियार सप्लाई के लिए उन्हीं शक्तियों पर निर्भर रहे हैं।

भारत की संसद जिसमें सभी पार्टियां मौजूद रही हैं भारत की जनता से निरन्तर झूठ बोलती रही हैं। उदाहरणतया भारत को दुनिया की गुट–निरपेक्ष शक्ति बताना, जबकि शुरू में अमेरिका एवं बाद में सोवियत गुट में शामिल रहना। इसी तरह डंकल ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करने को भारत की संसद में

Scanned with CamScanner

आर्थिक गुलामी का प्रतीक बताना परन्तु बाद में (डब्ल्यू टी ओ बनने के बाद) उसका कभी जनता के सामने जिक्र भी नहीं करना। सन् 1992 में नई आर्थिक नीति के तहत विश्व के तथाकथित उदारीकरण या वैश्वीकरण में शामिल करने वाली कांग्रेस सरकार ने कभी नहीं कहा कि अब हम आजादी के बजाए अन्तरनिर्भर विश्व व्यवस्था में शामिल हो रहे हैं। वर्तमान भारतीय जनता पार्टी एवं उसके समर्थक संगठनों ने हमेशा से स्वदेशी का प्रचार किया और उसी को सच्चा राष्ट्रवाद बताया परन्तु जब भी वे शासन में आये उन्होंने विकास के नाम पर सभी विदेशी कम्पनियों के लिए द्वार खोल दिए, उन्हीं से मेक इन इंडिया करवाने लगे। भारत की किसी राजनीतिक पार्टी, पत्रकार या बुद्धिजीवी ने पलटकर सवाल नहीं पूछा कि उस स्वदेशी नारे का क्या बना? लगता है कि दुनिया के विकसित देशों के कारपोरेट बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ, इतिहासकार दुनिया की जनता के सामने जितना झूठ परोसते हैं उसका दुगुना करके अल्प विकसित देशों के ये महानुभाव झूठ उंडेलते हैं।

दुनिया के औपनिवेशिक शासकों ने अपने राष्ट्रों में धर्म को व्यक्तिगत मुद्दा बनाते हुए राजनीति से दूर कर दिया था तथा धर्म को किसी भी आधुनिक विकसित राष्ट्र का आधार नहीं माना था। परन्तु इसके ठीक उलट भारतीय उपमहाद्वीप में धर्म के आधार पर दो देश (टू नेशन थ्योरी) बनाने का फैसला अंग्रेजों ने ही लिया ताकि दोनों देशों (भारत व पाकिस्तान) को कारपोरेट गुटों के जाल में फंसाकर यहां के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों की अबाध लूट जारी रखी जा सके। जो अभी तक जारी है। हमारे भारतीय उपमहाद्वीप की सभी पार्टियां इस धार्मिक कारपोरेटी जाल में समुद्री मछली की तरह फंसी हुई है एवं उपमहाद्वीप की जनता को संकीर्ण धार्मिक राष्ट्रवाद के नाम पर खुद भी छल रही है और अपने विश्व कारपोरेट आकाओं के साथ मिलकर हमारे ग्रह के जैव-जीवन को बर्बाद कर रही है।

इतिहास की अर्द्ध सत्यता (या झूठी) व्याख्याओं पर खड़ी सभी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां रात-दिन प्रचार करती है कि यही विकास है, यही सच्चा लोकतंत्र है, यही लोगों का, लोगों द्वारा, लोगों का शासन है। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है।

Scanned with CamScanner

आज दुनिया एवं हमारे देश की कारपोरेट शक्तियां जहां समस्त आर्थिक, सांस्कृतिक प्रक्रियाओं पर पूर्ण कब्जा जमाए हुए हैं वहीं विश्व स्तरीय राजनीतिक फैसले में दुनिया के लोगों को पूर्णतया दूर रखे हुए हैं।

सच्च तो यह है कि इसी प्रक्रिया के लिए (प्राकृतिक संसाधनों एवं लोगों पर नियंत्रण के लिए) दुनिया के हथियारों एवं सेना को बनाए रखना जरूरी है। आपसी कारपोरेट गुटीय प्रतिद्वंद्विता इसके लिए दूसरे नम्बर का स्थान रखती है, पहला स्थान लोगों पर नियंत्रण करना ही है। विश्व शांति ही इस जंजाल से मानव जाति को बाहर निकाल सकती है।

दुनिया की आम जनता को इस खुली-नंगी कानूनी गैर कानूनी सच्चाई को समझना पड़ेगा। दुनिया की वास्तविकता को सम्पूर्ण तौर पर समझे बगैर संकीर्ण नजरिए से हकीकत को समझना मानव जाति को महंगा पड़ेगा और पड़ रहा है। कहावत है कि हाथी को चारों तरफ से देखे बगैर उसके किसी एक अंग को समझना मुश्किल है। सर्वांगीण दृष्टि से देखने से ही हम राष्ट्रीय राजनीतिक आजादी, जनता के राजनीतिक अधिकार की महत्वता—यानि डेमोक्रेसी और चुनाव प्रक्रिया को समझ सकते हैं।

भारत की सन् 1947 के बाद की संसदीय राजनीति में राजनीतिक पार्टियों ने धन बल, सत्ता बल और फूट डालो राज करो की सामाजिक नीति के तहत लोगों की समझ को संकीर्ण जातिवादी, साम्प्रदायिक, छद्म राष्ट्रवादी एवं सबसे ऊपर व्यक्तिवादी बनाया है। इसी के बल पर भारत की जनता को गरीबी, बेरोजगारी, बदहाली एवं पर्यावरणीय बर्बादी में दुनिया का अव्वल देश बना दिया है।

तथ्य बताते हैं कि पिछले सभी संसदीय चुनावों की तुलना में सन् 2019 का चुनाव साम, दाम, दण्ड, भेद में प्रथम स्थान पर रहा है। यह चुनाव झूठ के प्रचार से भरा पड़ा है।

प्रथमतः, इस चुनाव का सबसे बड़ा झूठ व्यक्तिवाद के रूप में सामने आया है। भारत की जनता में व्यक्तिवाद इस हद तक प्रसारित किया गया और लगभग मनवाया गया है कि सामाजिक व्यवस्था का कोई महत्व नहीं है बल्कि व्यक्ति ही महत्वपूर्ण है और अगर यह मुखिया (प्रधानमंत्री) हो तो

Scanned with CamScanner

कहना की क्या है। जबकि सामाजिक व्यवस्था में ही प्रत्येक व्यक्ति (मुखिया का भी) की भूमिका होती है और हो सकती है, इससे भी आगे सामाजिक व्यवस्था का दारोमदार ना केवल मानव समाज पर निर्भर है बल्कि वह प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर है, मुखिया पर नहीं। परन्तु कहा गया कि हमारी राष्ट्रीय व्यवस्था को विकसित करने वाला एक सुपर हीरो 'प्रधानमंत्री' ही है और हो सकता है। उसका चुनाव करो।

पर्यावरण की बात मत करो, सामाजिक व्यवस्था की बात मत करो। रोजी रोटी तो क्या शुद्ध हवा की बात ही मत करो। पूछो इन सभ्य प्रचारकों व मीडिया से कि क्या आपका सुपर हीरो शुद्ध हवा के बिना दो मिनट जिन्दा रह सकता है? क्या बिना सामाजिक व्यवस्था के आपका सुपर हीरो प्रधानमंत्री बना रहेगा?

सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रचार में पर्यावरण एवं शुद्ध हवा का मुद्दा नहीं था और इनमें से ही हमें (जनता को) हमारे राष्ट्रीय राजनीतिक प्रतिनिधि सांसद चुनने थे जो अपने-अपने सुपर हीरो का प्रचार कर रहे थे। यानि पार्टियों के मुताबिक जनता की सामाजिक समस्याओं का हल उनके नेता की सद्इच्छा पर निर्भर करेगा। वही अब इस धरती के खुदा हैं, तुम तो राष्ट्र के नाम पर, विकास के नाम पर अपना बलिदान देने के लिए तैयार रहो और हमारे नेता का चुनाव करो।

दूसरा, इस चुनाव का बड़ा झूठ 'राष्ट्रवाद' का नारा था। जिसका आधार भारत-पाकिस्तान की दुश्मनी और सैनिक ताकत को बताया गया। जिस ताकत का मूल आधार वीटो पॉवर वाली महाशक्तियां और उनकी हथियार बनाने वाली कारपोरेट कम्पनियों के अलावा कोई और नहीं है। भारत और पाकिस्तान के व्यापारी और धनवान लोग तथा नेता मिलकर व्यापार चलाते हैं जबकि दोनों देशों के गरीब लोगों को सैनिक के तौर पर लड़ाया जाता है, कुर्बान करवाया जाता है। यह गतिविधि चुनाव के वक्त और तेजी से की जाती है। आम जनता की मानसिकता लड़ाई के पक्ष में बनाई जाती है क्योंकि शांति और विश्व शांति की धारणा दुनिया के इन कारपोरेट के लिए बहुत घातक है, अगर ऐसा होगा तो जनता पर इनका नियंत्रण नहीं रहेगा। अब समय दूर नहीं है जब भारत-पाकिस्तान-चीन ही नहीं दुनिया की

Scanned with CamScanner

जनता इस कारपोरेटी छद्म जाल को समझ कर विश्व शांति का झंडा बुलंद करेगी। मानव जाति एवं समस्त जैव-जगत की एकता सुनिश्चित करेगी।

तीसरा झूठ 'हिन्दू राष्ट्र' बनाने का है। हकीकत में समस्त दुनिया के राष्ट्र (भारत राष्ट्र सहित) कारपोरेट राष्ट्र हैं चाहे वह विकसित राष्ट्र हो या अल्प विकसित राष्ट्र हो। आज इस धरती पर कोई भी राष्ट्र धर्म के आधार पर नहीं है और ना हो सकता है। राष्ट्रों का आधार पूंजी का एजेण्डा है, धर्म आधार नहीं है। इस नारे का उद्देश्य जनता की मानसिकता को संकीर्ण ध्रुवीकरण पर धकेलकर उससे वोट प्राप्त करना और उस पर नियंत्रण कायम करना है।

चौथा झूठ 'सम्प्रदायवाद', 'जातिवाद', 'क्षेत्रवाद' का प्रचार है। इन धारणाओं की ऐतिहासिक चूलें हिल चुकी हैं। ये धारणाएं बची-खुची हैं जिनका राजनीतिक पार्टियां जनता में फूट डालकर उन पर नियंत्रण बनाए रखने में कर रही हैं। ये सब वाद पूंजी के वाद की सेवा में हाजिर हैं। इनका नागरिकों के जीवन में आर्थिक, राजनीतिक तौर पर कोई महत्व नहीं है।

पांचवां झूठ कि चुनाव जीतने वाले सांसद आम जनता के सच्चे प्रतिनिधि हैं और आम जनता में से ही है। यह कोरा झूठ इन तथ्यों से उजागर होता है कि वर्तमान 17वीं संसद में 88 प्रतिशत सदस्य करोड़पति हैं, भाजपा के 88 प्रतिशत, कांग्रेस के 84 प्रतिशत, द्रमुक के 96 प्रतिशत और तृणमूल कांग्रेस के 91 प्रतिशत करोड़पति उम्मीदवार सांसद बनने में कामयाब रहे। लोजपा और शिवसेना के सभी सांसद करोड़पति हैं।

नव निर्वाचित 542 सांसदों में से 539 सांसदों के हल्फनामों के विश्लेषण के आधार पर 159 सांसदों (29 प्रतिशत) के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, बलात्कार और अपहरण जैसे गंभीर आपराधिक मामले लंबित हैं। जबकि पिछली लोकसभा में गंभीर आपराधिक मामलों के मुकदमों में घिरे सदस्यों की संख्या 112 (21 प्रतिशत) थी, वहीं 2009 में ऐसे सांसदों की संख्या 76 (14 प्रतिशत) थी।

भाजपा के 303 में से 301 सांसदों के हल्फनामों के विश्लेषण में पाया कि प्रज्ञासिंह सहित 116 सांसदों (39 प्रतिशत) के खिलाफ मामले कोर्ट में

Scanned with CamScanner

चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस के 52 में से 29 सांसद (57 प्रतिशत) आपराधिक मामलों में घिरे हैं।

छद्म झूठ राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपनी पार्टी को जनता समर्थक बताना है। पिछले 70 साल का ही नहीं बल्कि केवल 5 साल (2014 से 2019 तक) का रिकार्ड ही देख लें। शासक पार्टी के किसी भी बड़े जन-विरोधी हमले में किसी विपक्षी पार्टी ने जनता को संगठित और आन्दोलित नहीं किया। नोटबन्दी जैसा डाका तो किसी राजा-बादशाह तक ने नहीं डाला। जी.एस.टी. जैसे कारपोरेटी कदम को तो कांग्रेस पहले ही उठाने का इरादा रखती थी जिसको भाजपा ने पूरा किया। किसी भी पार्टी के किसी भी नेता ने अपनी विधायिका के विशेष अधिकारों को छोड़ने, अपना वेतन नहीं बढ़ाने या दोहरी-तिहरी पेंशन प्राप्त करने का विरोध नहीं किया।

भाजपा की सरकार ने जब धन विधेयक के जरिये अपारदर्शी और गोपनीय चुनावी बॉण्ड लाकर चुनावों में धनबल को और अधिक बढ़ावा देने का कदम बढ़ाया तो किसी भी राजनीतिक पार्टी ने उसका विरोध नहीं किया। भारत के चुनावों में विश्व की समस्त कारपोरेट कम्पनियों की धनबल से सीधी दखलन्दाजी को एक तरफ कानूनी जामा पहनाना और भारत व विश्व की जनता से गुप्त रखने का सभी पार्टियों ने स्वागत किया है। मतलब साफ है कि प्रत्येक राजनीतिक पार्टी का अस्तित्व कम्पनियों पर निर्भर है जनता पर नहीं। कम्पनियां अपने धनबल से पार्टियां खड़ी कर सकती हैं जनता की मानसिकता को पार्टियों और मीडिया के माध्यम से बदल सकती हैं। अत: कोई भी राजनीतिक पार्टी जन समर्थक नहीं बल्कि सभी कारपोरेट समर्थक हैं।

एक तथ्य के मुताबिक वर्ष 2017-18 में 7 राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये से अधिक के चंदे में कुल 469.89 करोड़ रुपये मिले। भाजपा को इसमें 437.04 करोड़ रुपये मिले जबकि बाकी 6 दलों को 32.83 करोड़ रुपये मिले। भाजपा और कांग्रेस को सबसे अधिक चंदा प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट (पी ई टी) की ओर से मिला। धनबल के मुताबिक ही मीडिया प्रचार होता है। जिधर कारपोरेट का धनबल ज्यादा लगेगा उधर प्रचार का धुआं मुड़

Scanned with CamScanner

जायेगा। इसीलिए राजनीतिक पार्टियों को कारपोरेटों की जरूरत को पूरा करने की प्रतियोगिता में भाग लेते रहना पड़ेगा। राजनीतिक पार्टियां वर्तमान पूंजी की व्यवस्था से बंधी हैं, इनके बस में नहीं है कारपोरेट के खिलाफ जनता के मुद्दे या पर्यावरण के मुद्दे उठा सके। जनता इन्हें माफ करें, इनसे आशा ना करे।

आखिर में ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी ने पृथ्वी पर मानव एवं जैव-जीवन तथा पर्यावरण की रक्षा के लिए प्राकृतिक (जैविक-नैसर्गिक) खेती को बढ़ावा देने का जिक्र तक नहीं किया। भारत जैसे देश में प्रदूषणकारी औद्योगिक योजनाओं (लड़ाकू विमान व हथियार बनाने वाले उद्योगों, बुलेट ट्रेन सहित) एवं औद्योगिक गलियारों के निर्माण का विरोध नहीं किया है। रासायनिक खेती एवं जी.एम. खेती के माध्यम से पर्यावरण एवं खेती-किसानी को नुकसान पहुंचाने वाली एवं किसानों से कृषि भूमि हड़पने की कारपोरेटी योजना का विरोध नहीं किया है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में प्राकृतिक खेती एवं किसानों की सहकारी व्यवस्था को कम से कम 50 प्रतिशत बजट देकर कायम करते हुए देश में बेरोजगारी एवं पर्यावरण के प्रबंधन का नाम तक नहीं लिया है। जबकि देश में पर्यावरण के साथ-साथ बेरोजगारी, खेती-किसानी का संकट, जल संकट भयंकर रूप धारण करता जा रहा है।

अन्तिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि हमारी किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने हमारे देश के द्विपक्षीय व्यापार में अमेरिकी अड़ंगेबाजी और धौंस पट्टी का मुखर विरोध नहीं किया। भारत-पाकिस्तान के संबंधों को सुधारने का बयान तक नहीं दिया। जम्मू-कश्मीर समस्या के मानवीय हल का जिक्र तक नहीं किया।

सभी राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार व्यक्तिवादी तर्ज पर बहुत हल्के स्तर का रहा, जिसमें खास करके शासक भाजपा पार्टी और उसके सुप्रीम नेता मोदी ने झूठ और अवैज्ञानिक (अन्धविश्वासी) तथा अमानवीय घृणा को देश की जनता में भरपूर घोलने में सभी राजनीतिक पार्टियों का मार्गदर्शन किया। तभी तो नई संसद में पहली बार बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह सब भूल जाओ। संख्या बल में कौन कम है कौन ज्यादा

Scanned with CamScanner

इसको भी भूल जाओ। अब तो एक ही बात याद रखो कि हमारे देश में दो तरह के नागरिक हैं, एक वे नागरिक जो गरीब हैं और एक वे नागरिक जो गरीबी को हटाने वाले हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम सब सांसद गरीबी हटाने वाले नागरिकों (कारपोरेटों) के प्रतिनिधि हैं उनके विकास के लिए मिलकर काम करो।

III

लोक-सशक्तिकरण आधारित लोकतांत्रिक मॉडल के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण के बिन्दु

1. प्रकृति-मानव केन्द्रित राजनीति को एक ऐसी राजनीति की आवश्यकता है जो पूर्ण लोकतांत्रिक उसूलों, गतिविधियों और ढांचे पर आधारित हो। इस प्रकार की राजनीति संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था में विशेष वीटो शक्तियों के कानून को समाप्त करे और निर्णय लेने में अधिकतम संभव लोक-सशक्तिकरण को सुनिश्चित करे तथा पार्टी केन्द्रित शक्ति का आवश्यक मात्रा में कमी करे।

2. प्रकृति-मानव केन्द्रित राजनीतिक प्रक्रिया आम लोगों (एवं उनके जन संगठनों) द्वारा निर्देशित होनी चाहिए तथा उसका संचालन समर्पित प्रकृति-मानव केन्द्रित सामाजिक कार्यकर्ताओं (या उनके मोर्चे) द्वारा किया जाना चाहिए। चुनाव पूर्णतया स्वतंत्र हो जिसमें प्रत्येक को उम्मीदवार और मतदाता दोनों रूपों में भाग लेने का समान अधिकार है।

3. यह गांव/वार्ड से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक सामाजिक जीवन के तीन मूलभूत पहलुओं—राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक—के प्रबंध की शक्ति लोगों को देकर उनके सशक्तिकरण (या जनता के नेतृत्व वाले शासन) को प्रस्तावित करता है।

4. इसका राजनीतिक पहलू मांग करता है कि सभी स्तर पर (यानि अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य या क्षेत्रीय, जिला, ब्लाक और गांव) राजनीतिक सभा का गठन किया जाए, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कायम रहे तथा पूर्णतया लोकतांत्रिक सिद्धांतों, क्रियाकलापों और ढांचे पर आधारित हो। ऐसा

Scanned with CamScanner

मॉडल निर्णय लेने में भी अधिकतम संभव लोक सशक्तिकरण के सिद्धान्त को लागू करना आवश्यक बना देता है।

5. जनता के नेतृत्व वाले लोकतांत्रिक मॉडल के आर्थिक पहलू की आवश्यकता है कि एक तर्कसंगत और वास्तविक आर्थिकता के लिए सभी स्तरों पर विकास सभाएं स्थापित की जाए जिसकी धारणाएं, कानून एवं नियम दो उच्चतम प्राथमिकताओं (यानि, मानव जाति और पर्यावरण) तथा पांच सिद्धांतों (यानि, पर्यावरणीय संवर्धन, उचित समानता, उत्पादकता, जन नेतृत्वकारी लोकतंत्र तथा चहुंमुखी पारदर्शिता) की रोशनी में बनाए जाए।

6. इसके सांस्कृतिक पहलू की आवश्यकता है कि सभी स्तरों पर सांस्कृतिक सभाएं स्थापित की जाएं। यह ऐसे जीने के तरीके (या जीवन शैली) की मांग करता है जो बुनियादी मानवीय एवं पर्यावरणीय मूल्यों से भरपूर हो तथा लोगों के बीच में तर्कसंगत मानवतावाद एवं पर्यावरणवादी चिन्तन, व्यवहार एवं संगठन को विकसित करता हो।

7. सभी स्तरों पर राजनीतिक, विकास और सांस्कृतिक सभाओं द्वारा बनाये गये कार्यक्रमों और नीतियों को लागू करने के लिए अपने-अपने राजनीतिक, विकास और सांस्कृतिक क्षेत्र के आयोगों का चुनाव करना। संबंधित राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आयोग पांचों स्तरों पर प्रत्येक राजनीतिक, विकासोन्मुख और सांस्कृतिक प्रक्रिया के लिए अपनी-अपनी विशेषज्ञ कमेटियों का चुनाव करें।

राजनीतिक विशेषज्ञों का आयोग राजनीतिक मुद्दों, जैसे-कानून और व्यवस्था, अपराध रोकथाम, न्यायिक कार्यवाही से संबंध रखे; विकास विशेषज्ञों का आयोग आर्थिक, वित्तीय मसलों, जैसे—विकास, योजना, कृषि, उद्योग, सेवाएं, वित्त और बजट को देखें और सांस्कृतिक विशेषज्ञों का आयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, नैतिक मूल्यों एवं अन्य सांस्कृतिक विषय, जैसे—भाषा, संगीत, नृत्य, सिनेमा, इन्टरनेट आदि पर ध्यान दें।

8. यह पर्यावरणीय-मानवतावाद को मुख्य लोक प्रेरक पहलू के तौर पर आगे लाता है। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों और जगहों पर प्रचलित कुछ अन्य मानवीय रुझानों को अंगीकार करता है।

Scanned with CamScanner

9. यह अन्तर्राष्ट्रीय-मानववाद (विश्व नागरिक) को व्यक्ति की पहचान का मुख्य उसूल होने पर जोर देता है, साथ ही राष्ट्रीयता और नस्लीयता को दूसरे स्थान पर रखता है जबकि धार्मिक पहलू को व्यक्तिगत मामले का एक मुद्दा मात्र समझता है।

10. यह अवधारणा पैसे (या वित्त) को बड़ी चीज (पूंजी) की संज्ञा देने को रद्द करती है तथा हमारे ग्रह के प्राकृतिक संसाधन और मानवीय समाज को बड़ी चीज (पूंजी) की संज्ञा देती है। अत: इस अवधारणा के मुताबिक मानव समाज को हमारे ग्रह के प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों को प्रबंधित करके मानव सहित समस्त जैव-जीवन की पर्यावरणीय एवं सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।

IV

भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया में चुनाव सुधार के लोकतांत्रिक बिन्दु

वर्तमान भारतीय संसदीय चुनाव प्रणाली में राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक लोक सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित चुनाव सुधार करने आवश्यक हैं–

1. चुनाव प्रक्रिया में राजनीतिक पार्टियों को देशी-विदेशी कारपोरेट कम्पनियों द्वारा गुप्त एवं खुले चन्दे देने की कानूनी मान्यता रद्द की जाए।

2. लोकसभा उम्मीदवार के लिए 5000 वोटर तथा विधानसभा उम्मीदवार के लिए 1000 वोटर की जमानत आवश्यक की जाए तथा रुपये के रूप में जमानत राशि शून्य कर दी जाए।

3. सभी तरह के चुनावों में चुनाव प्रचार से लेकर चुनावी प्रक्रिया सम्पन्न करने की जिम्मेवारी सरकार की हो।

4. किसी भी उम्मीदवार, उसकी पार्टी व समर्थक को चुनाव प्रचार में धनबल लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।

5. समस्त मीडिया को कारपोरेट नियंत्रण से मुक्त किया जाए एवं उसके समाज विरोधी प्रचार को अपराध घोषित करते हुए प्रकृति-मानव

Scanned with CamScanner

समर्थक विचारों के मीडिया में तब्दील किया जाए।

6. धार्मिक विचारों को व्यक्तिगत विश्वास का मुद्दा मानते हुए उसे राजनीतिक मुद्दा बनाने को असंवैधानिक करार दिया जाए।

7. चुनाव का तरीका पूर्णतया पारदर्शी हो जिसमें कोई भी आम नागरिक (यानि वोटर) किसी भी तरह की हेराफेरी को चैक कर सके, किसी भी तरह के वोटर के संदेह को उचित निगरानी के माध्यम से विश्वास करवाया जाए। अविश्वास लायक किसी भी तकनीक (जैसे इ.वी.एम.) को हटाया जाए क्योंकि वह तकनीक आम नागरिक के समझ से बाहर है। आज के युग में जनता की समझ से बाहर तकनीक का दुरुपयोग कर पाना आसानी से संभव है।

8. जिस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार अथवा आपराधिक मामले में किसी भी न्यायालय में मुकदमा चल रहा हो उसे लोकसभा एवं विधान सभा की उम्मीदवारी के लिए अयोग्य माना जाए।

9. किसी भी उच्च पद (प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री पद) पर विराजमान व्यक्ति के लिए पद त्याग करना अनिवार्य किया जाए जब उसके अधिकार क्षेत्र में कोई बड़ी जन हानि या बड़ा दंगा हो जाए। ऐसे नेता पर उम्र भर के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश पर रोक लगा दी जाए।

10. अपने आपको सामाजिक या धार्मिक संगठन साबित करते हुए दूसरे संगठनों के प्रति दुर्भावना का प्रचार करते हो ऐसे संगठनों के सदस्यों की चुनाव में उम्मीदवारी पर रोक लगाई जाए।

11. धार्मिक आधार पर खुला प्रचार एवं भेदभाव करने वाले राजनीतिक संगठनों एवं व्यक्तियों को चुनाव के अयोग्य करार दिया जाए।

12. नकारात्मक मत देने (नोटा) के अधिकार को असरदायक बनाया जाए। इसके लिए अगर नोटा के वोट जीतने वाले उम्मीदवार से ज्यादा हों तो उस चुनाव को रद्द भी किया जाए तथा साथ ही पुराने सभी उम्मीदवारों का उस सीट पर दुबारा चुनाव लड़ना प्रतिबंधित किया जाए। नये उम्मीदवारों के साथ दुबारा चुनाव सम्पन्न करवाया जाए।

Scanned with CamScanner

13. किसी भी चुनाव में 50 प्रतिशत मतदान अनिवार्य किया जाए अन्यथा चुनाव को रद्द माना जाए एवं पुनः मतदान करवाया जाए।

14. जीतने वाले उम्मीदवार मतदान हुए मतों में से 50 प्रतिशत मत प्राप्त करना अनिवार्य हो।

15. चुने हुए उम्मीदवार को वापिस बुलाने का अधिकार हो। इसके लिए अगर उसके क्षेत्र के 20 प्रतिशत लोग कुछ समय बाद हस्ताक्षर करके वापिस बुलाने की मांग करे तो उस क्षेत्र में पुनः चुनाव करवाये जाएं।

16. चुना हुआ सदस्य कार्यपालिका के पद पर लगातार दो सत्र से अधिक नहीं रहे। खासकर उच्च पदों (यानि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति) दो बार से अधिक नहीं बन सकने का कानूनी प्रावधान किया जाए।

17. निष्पक्ष चुनाव आयोग का गठन किया जाए।

उपरोक्त चुनाव सुधार जनता के सशक्तिकरण में कुछ योगदान अवश्य देंगे।

सज्जन कुमार
सदस्य
प्रकृति-मानव केन्द्रित जन आन्दोलन, भारत

Scanned with CamScanner